

INDIAN COUNCIL OF MEDICAL RESEARCH
(DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH, GOVT. OF INDIA)

PRESS RELEASE

DHR AND DBT TO COLLABORATE FOR DELIVERABLE & AFFORDABLE HEALTH TECHNOLOGIES



New Delhi, 27 Sept. –Dr. V.M.Katoch, Secretary, Department of Health Research and Dr. M.K.Bhan, Secretary, Department of Biotechnology, Govt. of India have signed an MoU paving the way for collaborative biomedical research and development of affordable technologies for the health of the people. Several broad areas such as policy perspective, including economic analysis, and forecasting for affordable technologies for potential use in public health programs have been identified. A Joint Working Group will come into effect that would steer the programs for biomedical research in product development, process optimization and scale-up including evaluating the products for commercialization.

Dr. Bhan stated that DBT is already engaged in development and evaluation of vaccines, diagnostics, biomarkers, therapeutic bio-molecules and nutraceuticals. Dr. Katoch further mentioned that both DBT & DHR along with ICMR would utilize and compliment their facilities and infrastructure to facilitate the scientists to work on projects/programs of mutual interest and a consensus mechanism would be developed for harmonizing administrative and financial processes and approvals.

Dr. Bhan said that both sides would work together on transformative, interdisciplinary mega-projects and find out ways for speedy delivery of products at affordable cost to benefit the people of the country. Dr. Katoch also consented to constitute a small group of eminent scientific experts to strategize and oversee the projects/programs and also for conducting scientific audit to review the performance and progress of the collaborative projects. These projects would be strategic in nature keeping in view the national priorities. Both Dr. Bhan and Dr. Katoch expressed confidence that through this collaborative effort, a system would be developed for rapid delivery of useful health technologies/products to the people of the nation.

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली-२६

प्रेस विज्ञप्ति

सस्ती और कारगर तकनीकें विकसित करने का रास्ता प्रशस्त
-आई.सी.एम.आर.-बायोटेक्नोलॉजी विभाग का समझौता

नई दिल्ली, २७ सितम्बर -आई.सी.एम.आर. और बायोटेक्नोलॉजी विभाग के संयुक्त प्रयास से भारत के लोगों को अनेक प्रकार की सस्ती और कारगर हैल्थ टेक्नोलॉजी जल्द सुलभ करवाने का रास्ता प्रशस्त हो गया है। इस आशय के एक समझौते पर दोनों विभागों के सचिवों डा. विश्व मोहन कटोच और डा. महाराज कृष्ण भान ने दस्तखत किये। डा. कटोच ने बताया कि उक्त समझौते के तहत दोनों विभाग जहां स्वास्थ्य तकनीकों के विकास पर होने वाले खर्च को साझा करेंगे वहीं दोनों तरफ के वैज्ञानिकों को आपस में बातचीत करके ऐसी तकनीकें विकसित करने का मौका मिलेगा जो भारत के लोगों के स्वास्थ्य को ठीक से बनाये रखने में कारगर और सस्ती होने के अलावा बाजार में आसानी से मिल सकेंगी।

इस कार्यक्रम के तहत एक संयुक्त कार्यदल के गठन का फैसला लिया गया है जो कि साझा अनुसंधान परियोजनाओं पर नज़र रखेगा। इस दल के वैज्ञानिक समय-समय पर साझा परियोजनाओं की वैज्ञानिक समीक्षा भी करेंगे ताकि कार्य की प्रगति पर नज़र रखी जा सके। दोनों सचिवों का यह भी मानना है कि औपचारिकताओं से परे अनौपचारिक रूप से भी साझा योजनाओं के बीच काम करने वाले वैज्ञानिक सार्थक विमर्श और संवाद को चालू रख सकते हैं जिससे योजनाओं को जल्दी से पूरा करने में मदद मिलेगी।

संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं के अन्तर्गत टीकों का विकास, मां और शिशु के स्वास्थ्य की रक्षा, नई और कारगर दवाओं के विकास के लिये कारगर पाये गये रसायनिक अणुओं अर्थात् मोलिक्यूल्स से दवा विकसित करने करना और अनेक रोगों की शीघ्र पहचान के लिये नैदानिक तकनीकों के विकास की योजना है। बायोटेक्नोलॉजी विभाग अनुसंधान और स्वास्थ्य तकनीकें विकसित करने के अनेक मामलों में सशक्त है तो एपिडेमियोलॉजी अर्थात् जानपदिक रोग विज्ञान और क्लिनिकल ट्रायल्स जैसे मामलों में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् को बहुत अनुभव है। डा. भान ने कही कि साझा अनुसंधान को नतीजों तक पहुंचाने के लिये डी.बी.टी. को आई.सी.एम.आर. के ज्ञान और अनुभव की आवश्यकता है।

डा. भान ने आशा व्यक्त कि संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं के तहत विशाल और महत्वाकांक्षी अनुसंधान पर ही ध्यान दिया जायेगा लेकिन इसमें हमेशा यह ध्यान रखा जायेगा कि यह भारत के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों के अनुरूप हो।